

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ० बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 147/2017

अपीलान्त	बनाम	रेस्पोडेन्ट :-
कालुराम पुत्र नारायण जाति सरगरा निवासी निम्बोल तहसील जैतारण		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जैतारण

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :-

श्री लक्ष्मीनारायण वैष्णव, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से

—: निर्णय :-

दिनांक:- 15-11-18

अपीलान्त की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राज भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण संख्या 322/2016 में तहसीलदार जैतारण द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.10.2016 एवं अपील संख्या 37/2017 में न्यायालय जिला कलक्टर, पाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.04.2017 के विरुद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्त ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार जैतारण द्वारा अपीलाण्ट के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर ग्राम निम्बोल के खसरा नम्बर 234 रकबा 0.10 बीघा किस्म गै०मु० गोचर की भूमि पर अपीलाण्ट का अतिक्रमण मानते हुए नोटिस जारी किया। अपीलाण्ट अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित ही नहीं हुआ, इसके बावजूद भी अपीलाण्ट की उपस्थिति दर्ज की गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये जुर्माना आरोपित किया एवं आदेश बेदखली पारित किये, साथ ही पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए अपीलाण्ट्स को तीन माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त भूमि पर अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण माना, किन्तु पश्चातवर्ती अतिक्रमण को साबित करने हेतु पुरानी पत्रावली, खसरा गिरदावरी, खसरा परिवर्तनशील आदि की प्रतियां बतौर साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की तथा न ही ऐसी कोई मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिससे अपीलाण्ट का कब्जा साबित होता हो। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के बयान दर्ज करने बाबत कोई आदेश ही जारी



राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

नहीं किया, मात्र कागजी कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जो विधि विरुद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जो पूर्णतः विधि विरुद्ध है। तहसीलदार जैतारण द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपीलाण्ट्स द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को किसी प्रकार की राहत प्रदान नहीं करते हुए, जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि विरुद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावे एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि निम्बोल के खसरा नम्बर 234 रकबा 0.10 बीघा किस्म गै0मु0 गोचर की भूमि राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमण करने के कारण अपीलाण्ट के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए आदेश बेदखली पारित किये गये हैं। चूंकि अपीलाण्ट द्वारा किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमण की श्रेणी में परिलक्षित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। जैर अपील आदेश से सम्बन्धित प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम निम्बोल के खसरा नम्बर 234 रकबा 0.10 बीघा किस्म गै0मु0 गोचर की भूमि राजस्व रेकॉर्ड में सरकारी खाते में दर्ज है। पटवारी हल्का निम्बोल द्वारा तहसीलदार जैतारण के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि अपीलाण्ट द्वारा उपरोक्त भूमि पर कब्जा किया है, इस पर तहसीलदार जैतारण द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुए दिनांक 03.10.2016 की तारीख पेशी नियत की। उक्त आदेश की पालना में जो नोटिस जारी किया गया, वह अपीलाण्ट कालुराम से तामील करवाया गया, जो सम्यक तामील की परिभाषा में आने से तामील मानते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया। इस सम्बन्ध में पटवारी हल्का निम्बोल के बयान कलमबद्ध किये गये, जिसमें गवाह ने उक्त भूमि पर अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने के कथन किये। उक्त साक्ष्य का अपीलाण्ट द्वारा किसी भी रूप में पुनःपरीक्षण नहीं किया है। इस हेतु स्वयं अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब अथवा साक्ष्य प्रस्तुत करने का न तो समय चाहा गया। अपीलाण्ट द्वारा अपील के चरण संख्या 7 में जैर अपील विवादित आराजी पर स्वयं का बाडा होना स्वीकार किया है, जो जैर अपील विवादित आराजी पर उनके अतिक्रमण की स्वीकारोक्ति को प्रदर्शित करता है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0 3109/2011 जगपालसिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में दिनांक 28.01.2011




राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

को निर्णय पारित करते हुए कॉमन लैण्ड में अनाधिकृत कब्जे को खाली कराने के निर्देश दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त प्रकरण में प्रश्नगत भूमि कि किस्म गै0मु0 गोचर है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबन्धित है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा प्रकरण संख्या 322/2016 में तहसीलदार जैतारण द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.10.2016 एवं अपील संख्या 37/2017 में न्यायालय जिला कलक्टर, पाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.04.2017 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 15-11-2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(डॉ० बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली